माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक(एस) 6383/2008

याचिकाकर्ता **राजेश सिंह आर्या**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ शाशन व अन्य**

व

रिट याचिका(एस) क्रमांक 6675/2008 व रिट याचिका(एस) क्रमांक 288/2009 एवं 944/2009

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिकाएं)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति)

उपस्थित:- याचिकर्ताओं के ओर से क्रमशः श्रीमती शर्मिला सिंघई, श्री पराग कोटेचा, श्री आर.प्रधान, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, श्री पुनीत रूपरेल एवं श्रीमती सीमा सग्गर सिंह, अधिवक्ता।

शाशन की ओर से श्री वी.वी.एस.मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा एवं श्री घनश्याम पटेल।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(तीन मई 2010 को पारित)

1. रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008 और 6675/2008 तथा रिट याचिका (एस) क्रमांक 288/2009 और 944/2009 में समान तथ्य और समान विधिक प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, उक्त याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. **रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008**:- इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "पीएससी") द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (संक्षेप में "एडीपीओ") के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही, पीएससी को याचिकाकर्ता को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए और प्रश्नपत्र सेट-ए से प्रश्न क्रमांक 30, 32 और 64 के संबंध में संशोधित मॉडल उत्तर में दिए गए उत्तरों को पीएससी द्वारा प्रथम मॉडल उत्तर पत्रक के अनुसार सही करने का निर्देश दिया जाए।

3. **रिट याचिका (एस) क्रमांक 6675/2008:**- इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 21-10-2008 की चयन सूची (अनुलग्नक-पी/1) को रद्दकरने की मांग की है और आगे प्रार्थना की है कि पीएससी को तथ्यों पर आधारित सही उत्तरों के आधार पर एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

4. **रिट याचिका (एस) क्रमांक 288/2009:** इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 7-3-2008 की लिखित परीक्षा सहित सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्दकरने तथा एक नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने की मांग की है।

5. **रिट याचिका (एस) क्रमांक 944/2009:**- इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 21-10-2008 की चयन सूची (अनुलग्नक-पी/1) को रद्दकरने की मांग की है और आगे प्रार्थना की है कि पीएससी को तथ्यों पर आधारित सही उत्तरों के आधार पर एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. 2008 की रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383 में, प्रश्न क्रमांक 30 (सेट-ए) को हटा दिया गया था।

प्रश्न क्रमांक 32 इस प्रकार है:

> 32. 'ए' को राजमार्ग पर एक अंगूठी पड़ी मिलती है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। 'ए' उसे लेकर क्या करता है:
>
> (ए) आपराधिक दुर्विनियोग
>
> (बी) कोई अपराध नहीं
>
> (सी) चोरी
>
> (डी) आपराधिक न्यासभंग

संशोधित मॉडल उत्तर पत्रक के अनुसार प्रश्न क्रमांक 32 (सेट-ए) का उत्तर 'बी' है। सेट ए का प्रश्न क्रमांक 32, सेट डी के प्रश्न क्रमांक 2 के समान है।

सेट-ए में प्रश्न क्रमांक 64 इस प्रकार है:

> "निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज़ का उदाहरण नहीं है?
>
> (ए) अधिकारियों के बीच पत्र

(बी) मतदाता सूची

(सी) बीमा पॉलिसी

(डी) किसी प्रकरण में आदेश पत्र

संशोधित मॉडल उत्तर पत्रक के अनुसार प्रश्न क्रमांक 64 (सेट-ए) का उत्तर 'ए' है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सही उत्तर 'सी' है, न कि 'ए'। सेट-ए का प्रश्न क्रमांक 64, सेट-डी के प्रश्न क्रमांक 34 के समान ही है।

7. 2008 के रिट याचिका (एस) क्रमांक 6675 में याचिकाकर्ता ने किसी विशिष्ट प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिलाया है जिसमें कोई गलती पाई गई हो, सिवाय सामान्य कथन के कि पीएससी ने 6 उत्तरों के स्थान पर 9 उत्तर बदल दिए हैं तथा 1 प्रश्न हटा दिया गया है।

8. 2009 के रिट याचिका (एस) क्रमांक 288 में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि सेट-डी में प्रश्न क्रमांक 8 सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 भी सही नहीं है, क्योंकि संशोधित मॉडल उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर 'ए ' है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। याचिकाकर्ता के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम आपराधिकन्यायालय नहीं माना जा सकता। अंतिम आपराधिकन्यायालय सत्र न्यायालय है। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर 'ए ' है, जबकि उत्तर पुस्तिकाओं में इसका उत्तर 'डी ' बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 22 कोई विधिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 33 संदिग्ध है। संशोधित मॉडल उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 34 के संबंध में, उत्तर 'ए ' दर्शाया गया है, जबकि सही उत्तर 'सी ' है, अर्थात बीमा पॉलिसी। प्रश्न क्रमांक 52 का सही उत्तर 'ए ' है, लेकिन मॉडल उत्तर पुस्तिकाओं में इसे 'डी ' दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 58 और 79 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, विधि के नहीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रश्न क्रमांक 90 का सही उत्तर 'बी ' है, लेकिन संशोधित मॉडल उत्तर पत्रक में इसे 'सी ' दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, 26, 27, 28, 31, 72, 73, 76 और 100 प्रमुख प्रकरणों से संबंधित सामान्य प्रश्न हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम से बाहर का माना जा सकता है।

9. 2009 की रिट याचिका (एस) क्रमांक 944 में याचिकाकर्ता ने किसी विशिष्ट प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिलाया है जिसमें कोई गलती पाई गई हो, सिवाय सामान्य कथन के कि पीएससी ने परीक्षा आयोजित करने में कुछ अनियमितताएं की हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. संक्षेप में, इस प्रकरण के निर्णय के लिए तथ्य यह हैं कि दिनांक 12-3-2008 के विज्ञापन (रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008 से अनुलग्नक-पी/1) के प्रकाशन द्वारा, पीएससी ने एडीपीओ के 74 पदों पर चयन और भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। एडीपीओ पद के लिए लिखित परीक्षा 24-8-2008 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, पीएससी द्वारा दिनांक 20-8-2008 की प्रेस विज्ञप्ति (रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008 से अनुलग्नक-पी/4) के माध्यम से मॉडल उत्तर पत्रक प्रकाशित किया गया था। अभ्यर्थियों से पुनः आपत्तियाँ प्राप्त होने के बाद, संशोधित मॉडल उत्तर पत्रक प्रकाशित किया गया (अनुलग्नक-पी/6 से रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008 का अनुलग्नक-पी/6, पृष्ठ क्रमांक 87), जो पहले के मॉडल उत्तर पत्रों से भिन्न था, क्योंकि दोनों मॉडल उत्तर पत्रों में कई परिवर्तन हैं। संशोधित मॉडल उत्तर पत्रक में प्रश्न क्रमांक 30 को हटा दिया गया है, तथा प्रश्न क्रमांक 32 एवं 64 के उत्तर बदल दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। परीक्षा का परिणाम 21-10-2008 को घोषित किया गया (2008 की याचिका क्रमांक 6383 के अनुलग्नक-पी/6, पृष्ठ क्रमांक 86)। अतः, ये याचिकाएँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियम पीएससी को परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रश्नपत्र से कोई भी प्रश्न हटाने का अधिकार नहीं देते। पीएससी को लिखित परीक्षा आयोजित करने से पहले प्रश्नपत्रों की विशेषज्ञों द्वारा जाँच करवानी चाहिए थी। प्रश्न क्रमांक 32 और 64 के उत्तर भी बिना कोई ठोस और पर्याप्त कारण बताए बदल दिए गए हैं। लिखित परीक्षा में कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के दिए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि एक प्रतियोगी परीक्षा में एक अंक भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर पूरी तरह विचार किए बिना और अभ्यर्थियों को कोई सूचना दिए बिना ही परिणाम घोषित कर दिया गया।

12. इसके विपरीत, शासन की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति और पीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा ने यह तर्क किया कि शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीएससी ने एक मॉडल उत्तर पत्रक जारी किया और अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, पीएससी ने विशेषज्ञों से परामर्श किया और उनकी सलाह के अनुसार आपत्तियों का निर्णय लिया गया और संशोधित/सुधारित मॉडल उत्तर पत्रक जारी किए

गए, इस प्रकार, पीएससी की उक्त कार्रवाई को अवैध या गलत नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों पर गंभीरता और सम्यक तत्परता के साथ विचार किया गया था। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई मनमानी नहीं हुई। इस प्रकार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं थी और इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

13. पीएससी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिन्हा ने आगे कहा कि लिखित परीक्षा में भाग लेने के बाद और परीक्षा में असफल पाए जाने पर याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वैसे भी, याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पक्षकार/उत्तरवादी के रूप में शामिल नहीं किया है। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि संशोधित मॉडल उत्तरों को रद्दकरने के लिए कोई विशेष प्रार्थना नहीं है जो विषय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित हैं। आगे यह भी आग्रह किया गया कि उत्तरवादी पीएससी को 34 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुईं। सभी प्रश्नों को विषय विशेषज्ञों को भेजा गया था, और उनकी सिफारिशों और राय के आधार पर, यह पाया गया कि 10 प्रश्न गलत पाए गए, जिनमें से एक प्रश्न को हटाने की सिफारिश की गई, अर्थात सेट-ए में प्रश्न क्रमांक 30, सेट-बी में 20, सेट-सी में 10 और सेट-डी में 100 और उम्मीदवारों को अधिकतम अंक आवंटित किए गए। याचिकाकर्ताओं को उत्तरों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में उन्हें मॉडल उत्तरों की अनुमति नहीं होती, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए थे। आपत्तियाँ प्राप्त होने पर, उत्तर पुस्तिका में आवश्यक सुधार किए गए और कुछ प्रश्नों को हटा भी दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

15. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस) क्रमांक 6383/2008 में उत्तर पुस्तिका में तीन कमियाँ बताई हैं, अर्थात् प्रश्न क्रमांक 30, 32 और 64 (सेट-**A**)। इन तीन प्रश्नों में से, प्रश्न संख्या 30 को हटा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 32 का संशोधित मॉडल उत्तर सही प्रतीत होता है, और प्रश्न संख्या 64 का उत्तर संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसमें याचिकाकर्ता को

ऐसा उत्तर देना आवश्यक है जो अन्य उत्तरों से अधिक सही हो।

16. रिट याचिका (एस) क्रमांक 288/2009 में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि कई प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे, क्योंकि विज्ञापन में यह प्रावधान था कि प्रश्न भारत के संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम और विधिक सहायता न्यायाधिकरण अधिनियम से होंगे। याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं, लेकिन वे ऊपर बताए गए विषयों को छूते हैं। वैसे भी, चूंकि यह परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए इसे किसी विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता; हालाँकि, विज्ञापन की अनुसूची 1 के खंड 2 में दिया गया निर्देश सामान्य प्रकृति का है, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो विधिक विषयों से बाहर हो। कुछ अन्य प्रश्न संदिग्ध हो सकते हैं, लेकिन उक्त आधार पर पूरी परीक्षा को दोषपूर्ण घोषित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **सुभाष चंद्र वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**[1] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "यदि उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो भी अभ्यर्थियों को वैकल्पिक उत्तरों में से अधिक सही उत्तर चुनना होगा। वैसे भी, यह एक ऐसी कठिनाई है जो सभी अभ्यर्थियों को महसूस होती है।" इस प्रकार, यह कठिनाई प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को महसूस हुई और इस आधार पर इसे दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

18. **कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य**[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में त्रुटिपूर्ण और सही उत्तरों पर विचार करते हुए, जबकि बहुविकल्पीय उत्तर उपलब्ध थे, निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"**15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। सामान्यतः, कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से यदि वह प्रश्नपत्र तैयार करने वाला और परीक्षक रहा हो, यह विचार रखेगा कि प्रश्नपत्र तैयार

[1] 1995 सप्लीमेंटरी (1) एस.सी.सी 325

[2] (1983) 4 एस.सी.सी 309

करने वाले द्वारा दिए गए और विश्वविद्यालय द्वारा सही माने गए मुख्य उत्तर को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को प्रकाशित ही न किया जाए। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस प्रकरण में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इन प्रकरणों को देखने का यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि इन प्रकरणों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक सैकड़ों छात्रों का भविष्य जुड़ा है। यदि इस प्रकरण में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा जाता, तो इसका परिणाम और भी गंभीर होता क्योंकि बहुत से छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक दुखद स्थिति को उजागर कर दिया है

जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अवश्य ही खोजना होगा। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता ने उन्हें अपने द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली पर करीब से नज़र डालने का अवसर दिया है। जो विफल हुआ है वह कंप्यूटर नहीं बल्कि मानव प्रणाली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए श्री कक्कड़ ने तर्क दिया कि किसी भी मुख्य उत्तर की सत्यता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह पहली नज़र में गलत न हो। हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, अर्थात, यह ऐसा होना चाहिए जिसे उस विशेष विषय में पारंगत कोई भी उचित व्यक्ति सही न माने। इस प्रकरण में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त पाठ्यपुस्तकों द्वारा गलत साबित होता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में छात्र आमतौर पर पढ़ते हैं। ये पाठ्यपुस्तकें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़तीं कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।"

19. सुभाष चंद्र वर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"25.....(3)कई विवादास्पद प्रश्न सेट किए गए थे, और कुछ प्रश्नों के संबंध में, एक से अधिक उत्तर हो सकते थे। एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में, एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं। उम्मीदवारों को उत्तरों की बहुलता में से सबसे उपयुक्त उत्तर पर निशान लगाना आवश्यक है। प्रश्न और उत्तर मानक पुस्तकों के संदर्भ में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसलिए, यह कहना गलत है कि एक प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर होंगे। भले ही उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, उम्मीदवारों को वैकल्पिक उत्तरों में से वह चुनना होगा जो अधिक सही हो। किसी भी स्थिति में, यह सभी उम्मीदवारों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाई है।

श्री कमला कांत त्रिपाठी ने अपने प्रति-शपथ पत्र में केवल दो प्रश्नों की बात की है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 24% प्रश्न भ्रामक और विवादास्पद हैं, और कई प्रकार के प्रश्नों का पालन नहीं करते हैं। श्री एम.एल. वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया कि इस पहलू पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हम इस तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। सामान्यतः, उच्च न्यायालय को एक विशेषज्ञ निकाय नियुक्त करना चाहिए था और प्रश्नों की भ्रामक या विवादास्पद प्रकृति के बारे में उसकी राय लेनी चाहिए थी। सर्वविदित कारणों से, ऐसा नहीं किया गया। उसने केवल अपने समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं के कथन को स्वीकार करने का विकल्प चुना है। इस न्यायालय ने बार-बार ऐसे प्रकरणों को एक विशेषज्ञ निकाय को सौंपे जाने और उसकी राय लेने की ओर इशारा किया है, जिसका कारण यह है कि इस तरह के शैक्षणिक प्रकरणों में न्यायालयों के पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होती है। श्री एम.एल. वर्मा द्वारा उद्धृत कानपुर विश्वविद्यालय प्रकरण में, पृष्ठ संख्या 81-82 पर निम्नलिखित अवलोकन पाए जाते हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 316, कंडीका 16 और 17)

> " हम इस बात से सहमत हैं कि मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत साबित न हो जाए, और इसे तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिसंगतकरण की प्रक्रिया द्वारा

गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात, यह ऐसा होना चाहिए कि उस विशेष विषय में पारंगत कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसे सही न माने। इस प्रकरण में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों द्वारा गलत सिद्ध होता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश में छात्र आमतौर पर पढ़ते हैं। ये पाठ्यपुस्तकें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़तीं कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।

जिन छात्रों ने अपनी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ पुस्तकें निर्धारित हैं, और छात्रों को विषयों का जो ज्ञान है, वह उन पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी से प्राप्त होता है। ये पाठ्यपुस्तकें छात्रों के प्रकरणका पूरी तरह से समर्थन करती हैं। अगर यह संदेह का प्रकरण होता, तो हम निस्संदेह मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देते। लेकिन अगर प्रकरण संदेह के दायरे से बाहर है, तो छात्रों को मुख्य उत्तर के अनुरूप उत्तर न देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा, यानी ऐसा उत्तर जो गलत साबित हो चुका हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है।

शांतनु सिंह (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में, पृष्ठ 87 पर निम्नलिखित कहा गया है:

" संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में, इस न्यायालय के लिए इस प्रकरण की आगे जाँच करना संभव नहीं है और शपथपत्रों तथा अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, यह सिद्ध नहीं हुआ है कि 6 से अधिक प्रश्नों के उत्तर एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे, जिसके परिणामस्वरूप उन प्रश्नों को हल करने वाले अभ्यर्थियों को कोई नुकसान हुआ हो। विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया है कि विवादित 6 प्रश्नों पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाना चाहिए, और इस प्रकार, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद

विश्वविद्यालय ने स्वतः इस पहलू की जाँच की और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की कि छात्रों को इस कारण कोई नुकसान न हो।"

उपर्युक्त परिस्थितियों में, आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आयोग ने मूल्यांकनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे उन प्रकरणों में अभ्यर्थियों को पूरे अंक प्रदान करें जहाँ (क) अभ्यर्थी ने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाया हो और बॉक्स में सही उत्तर भी लिखा हो; (ख) अभ्यर्थी ने सही उत्तर के सामने केवल सही का निशान लगाया हो पर बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हो; और (ग) अभ्यर्थी ने बॉक्स में उत्तर लिखा हो पर सही उत्तर के सामने कोई सही का निशान नहीं लगाया हो। किसी भी विसंगति, अस्पष्टता या दोहराव के कारण अंक प्रदान करने में किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इसके अलावा, चूँकि कोई नकारात्मक अंकन नहीं था, इसलिए इस कारण किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.इसमें कोई विवाद नहीं है कि लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी। सफल उम्मीदवारों के आधार पर साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। पीएससी के अनुसार, लिखित परीक्षा की चयन सूची में, शुरू में विज्ञापित कुल पद 74 थे, जिन्हें बाद में संशोधित किया गया और 99 तक बढ़ा दिया गया। कुल 327 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क कि चूंकि नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है / तथाकथित चयनित उम्मीदवारों को आवश्यक पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है, गलत है। लिखित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था, और कुछ उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण है। यदि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के पीछे, उनके प्रतिकूल कोई निर्णय लिया जाता है, तो यह लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को काफी हद तक प्रभावित करेगा।

21. याचिकाकर्ताओं ने सफल अभ्यर्थियों को पक्षकार/उत्तरवादी बनाने का अवसर देने के बाद भी, इस आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वे प्रासंगिक पक्षकार नहीं हैं, क्योंकि अंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं हुई है। इस संबंध में,विधि सुस्थापित है कि ऐसी स्थिति में, आवश्यक पक्षों के न जुड़ने पर भी रिट याचिकाएँ खारिज हो जाती हैं। प्रस्तुत प्रकरणों में, सफल अभ्यर्थियों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी, कि उन्हें पक्षकार बनाना संभव नहीं था। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं ने भी जानबूझकर यह रुख अपनाया है कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। अतः, रिट याचिकाएँ केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं।

22. **अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम ए. आर्थर जीन एवं अन्य**[3] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने, सफल अभ्यर्थियों को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल न करने के प्रभाव पर विचार करते हुए, जिसमें चयन प्रक्रिया और उसके परिणाम शामिल थे, निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **" 13.** यद्यपि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को उनके अनंतिम चयन को दर्शाने वाले नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं मिलता है, वे निश्चित रूप से चयन सूची की रक्षा और बचाव में रुचि लेंगे। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अधिकरण के समक्ष, सफल उम्मीदवार जिनके नाम चयन के पैनल में शामिल थे, उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया था। विद्वान वकील का तर्क कि चूंकि पैनल में शामिल सफल उम्मीदवारों के नाम और विवरण नहीं दिए गए थे, इसलिए उन्हें पक्ष नहीं बनाया जा सकता, कोई बल नहीं रखता है। अधिकरण के समक्ष आवेदक विवरण प्राप्त करने का प्रयास कर सकते थे; कम से कम उन्हें कुछ सफल उम्मीदवारों को प्रतिनिधि की हैसियत से पक्षकार बनाना चाहिए था; यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार थे और यदि उन पर नोटिस की तामील में कोई कठिनाई थी, तो वे अधिकरण की अनुमति से कानून द्वारा अनुमत किसी भी तरीके से उन्हें तामील करने के लिए उचित कदम उठा सकते थे। इस न्यायालय ने **प्रबोध वर्मा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य** के प्रकरण में माना है कि राज्य के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में सेवा में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की भर्ती की वैधता पर सवाल उठाते हुए, उन प्रभावित व्यक्तियों या उनके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] (2001) 6 एस.सी.सी 380

प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना उन पर सुनवाई और प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जा सकता। उक्त निर्णय के कंडिका 50 में, उत्तरवादीगणों को पक्षकार बनाने के संबंध में इस न्यायालय के निष्कर्षों का सारांश देते हुए कहा गया है कि: (एससीसी पृष्ठ संख्या 288-89)।

> "किसी उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी रिट याचिका पर सुनवाई और निपटारा उन व्यक्तियों के बिना नहीं करना चाहिए जो उसके निर्णय से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होंगे, या कम से कम उनमें से कुछ प्रतिनिधि क्षमता में उत्तरवादी के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हों, यदि उनकी संख्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरवादी के रूप में शामिल करने के लिए बहुत अधिक है, और यदि याचिकाकर्ता उनसे जुड़ने से इनकार करते हैं, तो उच्च न्यायालय को आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के कारण याचिका को खारिज कर देना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23.**चन्द्र प्रकाश तिवारी एवं अन्य बनाम शकुंतला शुक्ला एवं अन्य**[4] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"32**. निष्कर्ष में, इस न्यायालय ने दर्ज किया कि आचरण द्वारा विबंधन का मुद्दा केवल तभी उपलब्ध माना जा सकता है जब कोई सटीक और स्पष्ट प्रतिनिधित्व हो और इसी आधार पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या कोई स्पष्ट आश्वासन था जिसने आश्वासित व्यक्ति को अपनी स्थिति या हैसियत बदलने के लिए प्रेरित किया - हालाँकि, वर्तमान स्थिति ऐसे निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती है और इसलिए हम आचरण द्वारा विबंधन के सिद्धांत से संबंधित डॉ धवन के तर्क से सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं। इस बिंदु पर यह ध्यान देने योग्य है कि आचरण द्वारा विबंधन का सिद्धांत भले ही लागू न हो, लेकिन यह साक्षात्कार/चयन में उचित भागीदारी पर नियुक्ति को चुनौती देने के अधिकार के संबंध में तर्क पर रोक नहीं लगाता है। यह एक ऐसा उपाय है जो वर्जित है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला के प्रकरण में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट

[4] (2002) 6 एस.सी.सी 127

शब्दों में कहा कि जब कोई अभ्यर्थी बिना किसी विरोध के परीक्षा में बैठता है और बाद में पाया जाता है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ है, तो उक्त परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

24. **के.एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य**[5] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"**75. रिट याचिकाओं को पक्षकार की सूची में आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति के आधार पर भी विफल होना पड़ता है। हालांकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का तर्क है कि वे केवल सीमित सीमा तक सूची को चुनौती दे रहे हैं, उनके तर्क को स्वीकार करने से चयन सूची का पूर्ण पुनर्गठन होगा। उम्मीदवारों को उनके वर्तमान रैंक से विस्थापित किया जाएगा; इसके अलावा, उनमें से कुछ 70 की चयन सूची से भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए, यह अनिवार्य था कि चयन सूची में सभी उम्मीदवारों को रिट याचिकाओं में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था, अन्यथा वे बिना सुने प्रभावित होंगे। समाचार पत्र में प्रकाशन इस दोष को ठीक नहीं करता है। केवल निर्दिष्ट संख्या में उम्मीदवारों को पक्षकार बनाया जाना था, अर्थात, 70। ऐसा नहीं है कि प्रभावित होने वाले लोगों की एक बड़ी, अनिर्दिष्ट संख्या है। ऐसे मामलों में, केरल उच्च न्यायालय के नियम 148 का सहारा नहीं लिया जा सकता है। यह नियम केवल तभी लागू किया जा सकता है जब बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हों, और यह उन उम्मीदवारों को विवरण के साथ इंगित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हमारे विचार में, रिट याचिकाएँ आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के कारण भी विफल होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **पंकज शर्मा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य**[6] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"**52. वर्तमान प्रकरण में, आयोग ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए थे। पुनः, जब उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि कुछ और कार्रवाई की आवश्यकता है और कुछ निर्देश

[5] (2006) 6 एस.सी.सी 395

[6] (2008) 4 एस.सी.सी 273

जारी किए, तो आयोग ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और जारी निर्देशों को स्वीकार कर लिया और उसे चुनौती नहीं दी। हमारी राय में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुचित या अतार्किक नहीं कहा जा सकता। वास्तव में, ऐसी स्थिति में, न्यायालय द्वारा हमेशा उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।"

26.प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर वर्णित कारणों से, रिट याचिकाएँ गुण-दोष के आधार पर तथा आवश्यक पक्षों के सम्मिलित न होने के कारण विफल होती हैं। अतः, रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

27.वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

सही/-

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

(अधिवक्ता अभिषेक पांडेय द्वारा अनुवाद किया गया)